Date 01-07-2020

कोविड–19 परीक्षण के लिए वायरोलॉजी प्रयोगशाला

भूमिका :– कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका इसके परीक्षण को बढ़ाकर कोविड–19 के शिकार लोगों की पहचान करना है। इस दिशा में एक नई पहल के अंतर्गत कार्य करते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) में कोविड–19 के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरूआत की गई है।

परीक्षा उपयोगी बिन्दु :–

- सुविधा एक 3-के बायोसैफिली लेवल (बीएसएल) का अनुसरण करती है। सुविधाओं को बायोसैफिली लेवल निर्धारित किया जाता है, जिस सुविधा के साथ रोगजनक कार्य करता है।
- ICMR दिशा–निर्देश कोविड–19 वायरस से निपटने के लिए बीएसएल 2 स्तर की सुविधा की सलाह देते हैं, लेकिन सुविधा एक उन्नत संस्करण है।
- सुविधा में एक 'नकारात्मक दबाव' होता है जिसमें एक सक्शन सुविधा होता है जो किसी भी एरोसोल को खींचती है और इसे फिल्टर के माध्यम से पारित करती है, जिसका उपयोग वायरस या बैक्टीरिया को छानने के लिए किया जा सकता है ताकि सुविधा को कोविड–19 परीक्षण के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।
- बीएसएल 3 स्तर की सुविधा भी सुसंस्कृत सुविधाओं में संक्रमण की संभावना को कम करती है।
- सुविधा की स्थापना से उत्तरप्रदेश की परीक्षण क्षमता बढ़ जाएगी जो वर्तमान में हर दिन लगभग 20,000 नमूनों का परीक्षण करती है।
- यह सुविधा पहले सप्ताह में एक दिन में 200 नमूनों की जांच के साथ शुरू होगी, लेकिन प्रतिदिन 500 नमूनों की माप की जाएगी।

पीएम एफएमई योजना लॉन्च

भूमिका :– आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFMF) योजना लॉन्च किया गया।

परीक्षा उपयोगी बिन्दु :–

- इस योजना को हरसिमत कौर बादल (केंद्रिय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री) द्वारा शुरू किया गया था। इससे पहले 20 मई, 2020 को इस योजना की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

- इस योजना से 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। योजना के तहत कुल निवेश का 35,000 करोड़ रूपये होगा।
- इस योजना के तहत देश भर में 8 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयाँ लाभान्वित होंगी।
- इय योजना का उद्देश्य देश में स्थानीय असंगठित खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों का समर्थन करना है।
- वित्त के रूप में सहायता, सहायता प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूत करना, राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि, आदिवासी जिलों में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल हैं।
- इस योजना के माध्यम से असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रयास किया जायेगा।
- इस योजना का कुल खर्च 10,000 करोड़ रूपये होगा। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक अगले पाँच वर्षों में लागू की जाएगी।
- केंद्र और राज्य सरकारें 60 : 40 के अनुपात में खर्च साझा करेंगी। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ, केंद्र सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत के अनुपात में होगा।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित होगी।

आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली

भूमिका :- पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत ने चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश समेत कई मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है।

परीक्षा उपयोगी बिन्दु :-

- यह मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन की सेना के किसी भी उतसावे की कार्रवाई की स्थिति में महज चंद सेकंद में ही करारा जवाब देने में सक्षम है।
- भारत ने यह कदम सीमा पर चीन के जंगी विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ाये जाने के बाद उठाया है।
- आकाश मिसाइल जमीन से हवा में हमला करने की मारक क्षमता रखती है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह सुरसोनिक मिसाइल है। इसका वजन 700 किलोग्राम है और गति 2.5 मैक है।
- मिसाइल की सबसे खात बात है कि यह 25 किलोमीटर के रेंज में किसी भी उड़ती चीज को भेदने में सक्षम है। इसे भारत का पैट्रियॉट कहा जाता है।

- आकाश मिसाइल चंद सेकंड में ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को तबाह कर सकती है। मिसाइल में मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिससे बेहद ऊँचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को धूल चटा सकती है।